भारत का निष्कर्षण पारदर्शिता चार्टर

प्रस्तावना

हम, नागरिक के रूप में, और नागरिक समाज संगठनों, नागरिक अभियानों, नेटवर्क, प्रभावित समुदायों, खदान श्रमिकों और यूनियनों के प्रतिनिधियों के रूप में भारत के प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण से संबंधित सभी प्रक्रियाओं में अत्यधिक पारदर्शिता की मांग करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। हम मानते हैं कि सभी प्राकृतिक संसाधन आम लोगों की संपत्ति और विरासत हैं, और राज्य हमारी ओर से एक ट्रस्टी की भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिकों के सर्वोत्तम हित में निर्णय लिए गए हैं और निकासी प्रक्रिया के निरीक्षण और निगरानी में नागरिकों की एक व्यवस्थित भूमिका हो सकती है, हम इस चार्टर पर हस्ताक्षर करते हैं और पैरवी और जुड़ाव के माध्यम से चार्टर को अक्षरश: लागू करने के लिए एक जीवंत जन अभियान का निर्माण करने का संकल्प लेते हैं।

I. संदर्भ

पारदर्शिता के सिद्धांत दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र का आधार बनते हैं। जबकि यह सच है कि पारदर्शिता की मांगों पर सहमति बनी है और इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया है, वर्षों बाद यह अभी भी व्यवहार में एक सिद्धांत है। दुनिया भर में सरकारें और नागरिक अभियान अभी भी प्रभावी और कार्यात्मक पारदर्शिता को व्यावहारिक वास्तविकता बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

भारत में पिछले दो दशकों में न्यूनतम सेवाओं के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए अधिकार-आधारित ढांचे की नयी सेवाओं के साथ, पारदर्शिता की भूमिका को सामाजिक सशक्तिकरण के लिए एक मौलिक पूर्व-आवश्यकता के रूप में और एक अंत के साधन और अपने आप में एक अंत, दोनों के रूप में मान्यता दी गई है। मजदूरी भुगतान में पारदर्शिता की मांग के लिए एक जन आंदोलन ने एक जीवंत और विविध अभियान का नेतृत्व किया जिसके कारण 2005 में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम पारित हुआ। तथ्य यह है कि श्रमिकों, कृषकों, छात्रों, पत्रकारों, शोधकर्ताओं, नौकरशाहों, किसानों, वकीलों और कार्यकर्ताओं सहित देश के लगभग साठ लाख नागरिक सूचना तक पहुँचने के साधन के रूप में आरटीआई का उपयोग करते

हैं और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराते हैं, यह पारदर्शिता की व्यक्तिगत और सामूहिक मांग का संकेत है जो लगातार बढ़ रही है।

प्राकृतिक संसाधन देश की एक जन संपदा हैं, वर्तमान में राज्य जीवित लोगों और आने वाली पीढ़ियों की ओर से साझा विरासत के ट्रस्टी की भूमिका निभा रहा है। वर्तमान पीढ़ी इस जन संपदा के संरक्षण, रखरखाव और बिक्री पर निर्णय ले रही है, जिसका परिणाम आने वाली पीढ़ियों को पूरी तरह से भुगतना होगा। यह देखते हुए कि भविष्य की पीढ़ियां अभी तक इस निर्णय लेने में भाग लेने में सक्षम नहीं हैं, यह जरूरी है कि वर्तमान में लिए गए निर्णय न केवल निष्पक्ष हों, बल्कि निष्पक्ष दिखाई भी दें, क्योंकि राज्य को अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

इसलिए राज्य को कानूनी और प्रशासनिक मानकों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए निष्कर्षण क्षेत्र में पारदर्शिता एक महत्वपूर्ण और गंभीर साधन है। भारत में निष्कर्षण उद्योग ने विकास, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और यहां तक कि चुनावी राजनीति पर बहस में अधिक हाई-प्रोफाइल भूमिका निभानी शुरू कर दी है। उदाहरण के लिए, बड़ी संख्या में समुदाय उस भूमि पर रहते हैं जहां खनिज संसाधन पाए जाते हैं, और उनके निष्कर्षण में बड़े पैमाने पर विस्थापन शामिल है। विस्थापन का सामना कर रहे लोगों के प्रतिरोध और चिंताओं ने देश में पारदर्शिता की बहस को एक अलग बनावट दी है। इसके अलावा, बड़े "घोटालों" का पता चला है जो खनन लाइसेंस और अनुबंध देने में भेदभाव प्रदर्शित करते हैं; इस तरह की भ्रष्ट प्रथाओं ने वास्तविक उत्पादन शुरू होने पर राज्य के लिए सर्वोत्तम से कम राजस्व उत्पन्न किया है। इसलिए भारत में निष्कर्षण की राजनीतिक अर्थव्यवस्था जीवन, आजीविका और राज्य के राजस्व को प्रभावित करती है।

निष्कर्षण उद्योग द्वारा सरकार को किए गए भुगतानों के बारे में नागरिकों की जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनिवार्य प्रकटीकरण मानक के लिए वैश्विक आंदोलन - जिसके लिए दुनिया की कुछ सबसे बड़ी निष्कर्षण कंपनियों को जिस देश में वे काम कर रहे हैं, प्रत्येक देश में प्रत्येक परियोजना के लिए सरकारों को किए गए भुगतानों को प्रकाशित करने की और कंपनियों और सरकारों दोनों को जवाबदेह ठहराने के लिए नागरिकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस डेटा का उपयोग करने के लिए के लिए सक्षम करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए वेदांत रिसोर्सेज

जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, विदेशी सरकारों को किए गए रॉयल्टी भुगतान के लिए बाध्य है और इसका खुलासा करता रहा है, जिसमें यह यूरोपीय संघ (ईयू) में कानून के अनुसार निकासी संचालन चला रहा है।

जबकि भुगतानों का अनिवार्य प्रकटीकरण एक खुले और जवाबदेह निष्कर्षण क्षेत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, इसलिए यह आकलन करने कि क्या किए गए भुगतान उचित और पर्याप्त थे, जो लागतों को ध्यान में रखते हुए किये गए थे, नागरिकों को अन्य प्रकार की सूचनाओं तक पहुंच की आवश्यकता होती है। इसलिए इस चार्टर में निष्कर्षण कंपनियों द्वारा सरकारों को भुगतान के अनिवार्य प्रकटीकरण के अलावा, लाइसेंस और अनुबंधों की प्राप्ति की प्रक्रियाओं, अनुबंध की शर्तों और लाभकारी स्वामित्व की जानकारी के संबंध में अधिक पारदर्शिता का आह्वान और साथ ही साथ नीति और निर्णय लेने और प्राकृतिक संसाधन प्रशासन सिद्धांतों और कानूनों की निगरानी के बारे में अधिक पारदर्शिता और सहभागिता शामिल है।

हमने यहां ध्यान दिया कि पारदर्शिता के लिए हमारा आह्वान खान मंत्रालय के आधिकारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जैसा कि सतत विकास ढांचे (सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क) में व्यक्त किया गया है, जिसमें कहा गया है कि "यहां तक कि जहां सूचना साझा की जाती है, वहां भी सूचना अक्सर अग्रिम संवेदनशील मामलों से निपटने के बजाय सौम्य मुद्दों तक सीमित होती है। अधिकांश सततता रिपोर्ट प्रभाव शमन उपायों या उनके समुदाय के लिए की गई प्रतिबद्धताओं पर प्रदर्शन को नहीं छूती हैं। इसलिए कंपनियों के सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक प्रदर्शन पर संरचित जानकारी प्रदान करना और पारदर्शी होने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना महत्वपूर्ण है।"

II. भारत का निष्कर्षण चार्टर और इसके उद्देश्य

हालांकि ऐसे कई कानून, नीतियां और न्यायिक आदेश हैं जो भारत में निष्कर्षण प्रक्रिया के कई चरणों की रिपोर्टिंग और सूचना साझाकरण को नियंत्रित करते हैं, सूचना प्रकटीकरण और पारदर्शिता का ऐसा कोई न्यूनतम मानक नहीं है जिसके द्वारा निष्कर्षण उद्योग बाध्य है। इसके अलावा, लीज/परियोजना स्तर पर सूचना साझा नहीं की जाती है; एक साझा मंच का अभाव है जो सूचना के एकल भंडार के रूप में काम कर सकता है; और पारदर्शिता मानदंडों के अनुपालन पर स्वतंत्र निरीक्षण का अभाव है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सत्ता के मौजूदा ढांचे

में, सूचना तक पहुंचने के तरीके में नागरिकों और कंपनियों की क्षमता के बीच अंतर्निहित असमानता है।

इसलिए निष्कर्षण उद्योग की गतिविधियों के बारे में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक डोमेन में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आह्वान करने और जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराने के लिए नागरिकों को सूचना का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए "भारत निष्कर्षण पारदर्शिता चार्टर" विकसित करने की आवश्यकता है। चार्टर का उद्देश्य है:

• पारदर्शिता और सूचना प्रकटीकरण के न्यूनतम सिद्धांतों को निर्धारित करना जो निष्कर्षण उद्योग को नियंत्रित करे

• निष्कर्षण के प्रत्येक चरण से संबंधित सूचना की प्रकृति की पहचान करना यानी पट्टों का आवंटन, अनुमोदन और मंजूरी, उत्पादन, रिपोर्टिंग और भुगतान - जिसे सार्वजनिक डोमेन में प्रकट किया जाना चाहिए ताकि प्रभावित समुदाय और नागरिक, उद्योग को जवाबदेह ठहरा सकें।

• क्षेत्र के संचालन से संबंधित ज्ञान का लोकतंत्रीकरण करने का प्रयास। यह प्रयास किया जाना चाहिए कि सरकारी अभिलेखों को समझने के लिए ज्ञान का एक निकाय विकसित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे जवाबदेह ठहराने में सहभागी हो सकें।

• पैरवी, कानूनी हस्तक्षेप और क्षमता निर्माण के माध्यम से इस तरह के खुलासे को साकार करने के लिए एक अभियान के लिए आगे की योजना बनाना

उदाहरण के लिए, 2016-17 तक स्वयं भारत सरकार ने बताया कि देश में 96,089 अवैध खदानें चल रही हैं, जो पूरी तरह से औपचारिक रिपोर्टिंग तंत्र से बाहर हैं। ऐसे संदर्भ में, एक ऐसा पारदर्शिता ढाँचा बनाने की बड़ी आवश्यकता है जो नागरिकों और प्रभावित समुदायों को पट्टाधारकों और राज्य को जवाबदेह ठहराने में सक्षम बनाए।

एक चार्टर विकसित करने के लिए जो उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा कर सके, यह अनिवार्य है कि इसकी सामग्री नागरिकों से निकले और सार्थक परामर्श की प्रक्रिया के माध्यम से निष्कर्षण उद्योग के साथ उनके अनुभव को ध्यान में रखे।

इसके लिए एनवायरोनिक्स ट्रस्ट और एसआर अभियान के सहयोग से जयपुर, राजस्थान और रांची, झारखंड में बहु-हितधारक परामर्श आयोजित किए गए। इन परामर्शों में खनिज निष्कर्षण पर काम कर रहे 35 नागरिक समाज संगठनों और गैर सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले, स्वतंत्र विशेषज्ञों, पत्रकारों के साथ-साथ खनन विभागों और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में काम कर रहे सरकार के प्रतिनिधियों सहित लगभग 130 कार्यकर्ताओं की भागीदारी देखी गई। सक्रिय खनन स्थलों और प्रभावित आसपास के गांवों का दौरा किया गया। इस अभ्यास के दौरान खनन कंपनियों को अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में काम कर रहे जमीनी स्तर के संगठनों और प्रभावित समुदायों के साथ बातचीत भी हुई।

III. पारदर्शिता और सूचना प्रकटीकरण के न्यूनतम सिद्धांत

इस प्रयास के तहत हुए परामर्शों और नागरिकों, अभियानों और सीएसओ के संघर्ष और अभ्यास से उत्पन्न वर्षों के अनुभव के आधार पर, सत्ता की संरचनाओं को जवाबदेह ठहराने की जानकारी तक पहुंचने के लिए, निम्नलिखित पारदर्शिता के न्यूनतम सिद्धांतों के रूप में उभरे हैं जिन्हें भारतीय निष्कर्षण उद्योग के लिए सूचना प्रकटीकरण ढांचे को नियंत्रित करना चाहिए।

1) **निष्कर्षण से संबंधित सभी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में होनी चाहिए।**

निष्कर्षण से संबंधित सभी जानकारी सार्वजनिक सूचना है और इसे लोगों के सामने प्रकट किया जाना चाहिए। किसी भी ऐसे प्रयास को रोकना चाहिए जो किसी नागरिक को सूचना तक पहुँचने से प्रतिबंधित/बहिष्कृत कर सकता है या ऐसा करने की उनकी आवश्यकता को साबित करने से रोकता है। निष्कर्षण के सभी चरणों में पारदर्शिता और रिकॉर्ड रखरखाव के प्रशासनिक प्रावधानों को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 में निर्धारित मानकों और सूचना प्रकटीकरण की आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए।

2) **उद्योग को उसके मानदंडों के प्रति जवाबदेह बनाने में नागरिकों की सुविधा के लिए निष्कर्षण (निकासी) के सभी चरणों में पारदर्शिता की आवश्यकता है।**

इसलिए प्रकटीकरण में अधिकारों, प्राप्तियों और खर्चों, मानदंडों, अनुबंध की शर्तों, मानकों, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और लिए गए निर्णयों के औचित्य, अपील की संभावनाएं, नागरिकों को सशक्त

बनाने के लिए शिकायत निवारण के रास्ते की व्यापक समझ और प्रकटीकरण शामिल होना चाहिए।

3) सभी नागरिकों के लिए सूचना की समान और खुली पहुंच होनी चाहिए।

नागरिकों के प्रति जवाबदेही को सक्षम करने के लिए एक ढांचे के भीतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसलिए, योजना बनाने और निर्णय लेने के चरण में पारदर्शिता की आवश्यकता होती है ताकि नागरिक और प्रभावित समुदाय परामर्श में सार्थक रूप से भाग ले सकें। कार्यान्वयन और रिपोर्टिंग के स्तर पर भी पारदर्शिता की आवश्यकता होती है, ताकि नागरिक और प्रभावित समुदाय निरंतर सार्वजनिक सतर्कता बनाए रख सकें और सत्यापित कर सकें कि जो रिपोर्ट किया जा रहा है वह वास्तव में सच है या नहीं।

4) विकेंद्रीकरण और निर्णय लेने के लिए कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन

सूचना के अनिवार्य प्रकटीकरण के सभी मानदंडों को वन अधिकार अधिनियम, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची और संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के मौजूदा कानूनी प्रावधानों का पालन करना चाहिए।

5) कुछ हाशिए के समूहों को सूचना तक पहुँचने के लिए विशेष रूप से सशक्त बनाने और सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है।

सूचना का प्रकटीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जाना चाहिए। आवंटन, मंजूरी, योजना, उत्पादन और रिपोर्टिंग के संबंध में राज्य द्वारा बनाए गए सभी रिकॉर्ड वास्तविक समय, लेनदेन आधारित 'प्रबंधन सूचना प्रणाली' (एमआईएस) के आधार पर तैयार किए जाने चाहिए जो सभी के लिए खुला होना चाहिए। इस तरह की प्रबंधन सूचना प्रणाली को नागरिकों और लाभार्थियों के हितों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए ताकि व्यापक उपयोग और पहुंच को सक्षम बनाया जा सके। एमआईएस वास्तविक समय, लेनदेन आधारित और सभी के लिए खुला होना चाहिए। उत्पन्न रिपोर्ट मशीन पठनीय और पहुंच के लिए मुक्त होनी चाहिए। इसके अलावा, सूचना का प्रकटीकरण विशेष प्रपत्रों और प्रारूपों के माध्यम से ग्राम स्तर पर दीवार पेंटिंग, नोटिस बोर्ड आदि के माध्यम से भी किया जाना चाहिए।

6) **सभी निर्णय लेने का खुलासा सभी इच्छुक हितधारकों के बीच सार्वजनिक डोमेन में किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि निर्णय न केवल निष्पक्ष हों बल्कि निष्पक्ष भी दिखाई दें।**

इस आशय के लिए, आरटीआई अधिनियम, की धारा 4(1) (सी), जो राज्य को "महत्वपूर्ण नीतियां बनाने या जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करने" को अनिवार्य करती है और धारा 4 (1) (डी), जो राज्य को "प्रभावित नागरिकों को अपने प्रशासनिक और अर्ध-न्यायिक निर्णयों के लिए कारण प्रदान करने" को अनिवार्य करती है इसे निष्कर्षण के सभी चरणों पर लागू किया जाना चाहिए।

7) **यह स्वीकार करते हुए कि, सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, सूचना प्रदान करने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के तरीके दोनों दूषित या अवरुद्ध हो सकते हैं, कई तरीकों और मार्गों का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि लोगों तक और लोगों से सूचना के मुक्त प्रवाह को रोकने को उत्तरोत्तर कठिन बनाया जा सके।**

प्रकटीकरण के तरीकों की बहुलता में राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर सूचना का प्रकटीकरण भी - संचयी और अलग-अलग दोनों स्तरों पर शामिल होना चाहिए। इसमें परियोजना-दर-परियोजना के आधार पर पट्टाधारकों को सरकारों को अपने भुगतान प्रकाशित करने की आवश्यकता शामिल है।

8) **राज्य द्वारा किसी मौजूदा या संभावित बोलीदाता या पट्टाधारक को उपलब्ध कराई गई सूचना नागरिकों को एक साथ उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किसी भी संस्था, व्यक्ति या निगम को खनिजों और उसके वितरण से संबंधित विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी प्राप्त करने में सक्षम नहीं होना चाहिए।**
9) **प्रकट की जा रही सूचना की प्रामाणिकता को सत्यापित करने और कई स्रोतों से डेटा को त्रिकोणीय करने में नागरिकों की सुविधा के लिए स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा सोशल ऑडिट जैसा संस्थागत तंत्र होना चाहिए। इस तरह के ऑडिट से निकलने वाले निष्कर्षों में कानूनी रूप से स्वीकृत सुधारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह, राज्य, पट्टाधारकों और नागरिकों के बीच नियमित आधार पर संवाद के लिए संस्थागत मंच होना चाहिए**

ताकि चिंता के मुद्दों को चिह्नित किया जा सके और समयबद्ध निर्णयों और संकल्पों पर आपसी सहमति से पहुंचा जा सके।

10) **प्रकटीकरण मानदंडों को पूरा करने के लिए निष्कर्षण उद्योग के अनुपालन की स्वतंत्र तरीके से निगरानी की जानी चाहिए। सूचना का खुलासा न करने या सूचना के अप्रामाणिक प्रकटीकरण को दंडित किया जाना चाहिए**

iv. खुलासा की जाने वाली जानकारी

सूचना के बुनियादी बिंदु जो सार्वजनिक डोमेन में होने चाहिए और ऊपर बताए गए सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं, जो निष्कर्षण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए पहचाने गए थे। वे इस प्रकार हैं:

1. **अन्वेषण और पूर्वेक्षण:**

यह देखते हुए कि यह किसी भी समुदाय में निष्कर्षण प्रक्रिया की शुरुआत का प्रतीक है, यह अनिवार्य है कि नागरिक, समुदाय और स्थानीय हित समूह इस चरण के बारे में सतर्क रहें और पट्टे के किसी भी संभावित अनुदान के तौर-तरीकों के बारे में जागरूकता हासिल करें। यह निष्कर्षण प्रक्रिया का एक चरण है जिस पर ज्यादातर आम जनता द्वारा बड़े पैमाने पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जो राज्य और संभावित पट्टाधारक के बीच निहित संबंधों के पक्ष में जाता है। इस चरण के संदर्भ में, निम्नलिखित जानकारी का सार्वजनिक डोमेन में होना आवश्यक है:

i. बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत संभावित योजनाएं
ii. अन्वेषण और पूर्वेक्षण के लिए दिए गए ठेके
iii. नियम, शर्तें और मानदंड जिनके तहत अन्वेषण किया जा सकता है
iv. उन सभी क्षेत्रों की सूची जहां अन्वेषण और पूर्वेक्षण वर्तमान में चल रहा है

2. **नीलामी और आवंटन:**

निष्कर्षण के इस चरण से संबंधित पर्याप्त और समय पर सूचना होना कि राज्य और पट्टाधारक के बीच हुई अनुबंध की शर्तों और समुदाय और पर्यावरण के लिए यह किस कीमत पर हुई, इसके बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है। ज्यादातर ऐसा होता है कि पट्टाधारक और राज्य के बीच अनुबंध तैयार किए जाते हैं, और संचालन के लिए मंजूरी मांगी जाती है, जिससे यह फालतू का अभ्यास बन जाता है, क्योंकि यह पहले से ही एक असफल उपलब्धि है। इसलिए यह मांग की

जाती है कि राज्य द्वारा नीलाम की जाने वाली भूमि का सार्वजनिक डोमेन में खुलासा किया जाना चाहिए, और जब तक पूर्व सहमति स्थापित नहीं हो जाती है, भूमि को पट्टे पर नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, नीलामी और आवंटन प्रक्रिया निष्पक्ष, किफायती और कुशल है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को सार्वजनिक डोमेन में साझा करने की आवश्यकता है। इस चरण के संदर्भ में, निम्नलिखित सूचना का सार्वजनिक डोमेन में होना आवश्यक है:

(i) भूमि जो राज्य नीलामी करने का इरादा रखता है और मौजूदा भूस्वामियों / निवासियों से सहमति का प्रमाण

(ii) अपेक्षित उत्पादन, अनुमानित राजस्व, पर्यावरण पर प्रभाव, भूविज्ञान और आजीविका पूर्वकल्पित अंतर्निहित प्रस्तावित नीलामी के उद्देश्य का विवरण

(iii) "नो गो एरिया" की सूची जहां पर्यावरण, भूविज्ञान और बस्तियों की रक्षा के लिए अन्वेषण और खनन नहीं हो सकता है

(iv) अन्वेषण और नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाली राजपत्र अधिसूचना

(v) निष्कर्षण से संबंधित सभी कैबिनेट निर्णय

(vi) उन बोलीदाताओं की सूची जिन्होंने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है और निष्कर्षण में उनका पिछला प्रदर्शन; और बोलीदाताओं के खिलाफ चल रहे और पिछले मुकदमे

(vii) भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा दर्ज देश के विभिन्न भौगोलिक स्थानों में खनिजों के वितरण और उनके स्थान से संबंधित जानकारी

(viii) पट्टाधारकों की सूची जिन्हें लाइसेंस प्रदान किया गया है और उनका विवरण

(ix) पट्टाधारक का सच्चा लाभकारी स्वामित्व

(x) माइनिंग लीज डीड और अनुबंध की शर्तों के बीच हुई सहमति

(xi) प्रत्येक पट्टे के लिए "खनन विकास सह संचालक" की नियुक्ति का विवरण, और जिन शर्तों के तहत यह नियुक्ति की गई थी

(xii) संचालन चलाने के लिए राज्य द्वारा दी गई विशिष्ट सब्सिडी, कर विराम और कर प्रोत्साहन का पट्टाधारक वार विवरण

3. भूमि का अधिग्रहण:

यह देखते हुए कि बड़ी संख्या में समुदाय, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, भूमि जोत के शीर्ष पर रहते हैं, जिसके तहत खनिज पाए जाते हैं, भूमि का अधिग्रहण निवासियों और बस्तियों की सामाजिक-राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर अपरिवर्तनीय परिणामों के साथ एक अभ्यास बन जाता है। 2013 में पारित भूमि अधिग्रहण, पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वास अधिनियम में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार, अधिग्रहण से पहले पारदर्शिता और सूचित सहमति सुनिश्चित करने के प्रावधानों को शुरू करके भूमि अधिग्रहण करने वाली कंपनी और उनकी भूमि से विस्थापित होने वालों के बीच शक्ति के समीकरण को संतुलित करने का किया गया प्रयास है। इस चरण के संदर्भ में, निम्नलिखित जानकारी का सार्वजनिक डोमेन में होना आवश्यक है:

i. भूमि अधिग्रहण का उद्देश्य और अवधि
ii. प्रभावित परिवारों की सूची और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति
iii. प्रभावित भूमि जोतों की सूची और भूमि उपयोग की उनकी मौजूदा श्रेणी
iv. भूमि अधिग्रहण के लिए सूचना
v. 'सामाजिक प्रभाव आकलन' करने वाली इकाई का विवरण और उसके संदर्भ की शर्तें
vi. सामाजिक प्रभाव आकलन की अनुसूची और जन सुनवाई की तिथि
vii. सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट
viii. प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति/परिवार को दी जाने वाली राहत, पुनर्वास और मुआवजे का विवरण
ix. ग्राम पंचायत (सामुदायिक भूमि के लिए) और व्यक्तियों (निजी भूमि के लिए) के अधिग्रहण के लिए सहमति का प्रमाण
x. उन सभी भूमि जोतों की सूची जो अधिग्रहित की गई है/निष्कर्षण के कारण अधिग्रहण की प्रक्रिया में है
xi. अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे की दर निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त मानदंड
xii. भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के रूप में भूमिधारकों को दिए गए रोजगार पैकेज का विवरण

4. मंजूरी प्राप्त करना:

पर्यावरण, प्रदूषण, वन और वन्यजीव प्राधिकरणों द्वारा संचालित करने के लिए मंजूरी और सहमति उन व्यावहारिक शर्तों को निर्धारित करती है जिनका पालन करना पट्टाधारक के लिए अनिवार्य किया जाता है, जिसके अधीन संचालित करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है। पट्टाधारकों द्वारा मंजूरियों में निर्धारित शर्तों के अनुपालन की निगरानी सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा की जाती है। हालांकि, यह देखते हुए कि इन शर्तों का विवरण केवल पट्टाधारक और निष्कर्षण अधिकारियों को ही पता है, इस निगरानी के लिए सतही हो जाने और इससे समझौता किये जाने के लिए प्रोत्साहन है (जैसा कि वास्तविक अनुभव में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है)। यह आवश्यक है कि संचालन की शर्तों को सार्वजनिक किया जाए क्योंकि स्थानीय समुदायों के पास जो भी है उनका सबसे अधिक दांव पर है और यह निगरानी करने के लिए सबसे अच्छी तरह से सुसज्जित हैं कि क्या इन शर्तों को पूरा किया जा रहा है। इस चरण के संदर्भ में, निम्नलिखित सूचना का सार्वजनिक डोमेन में होना आवश्यक है:

I. 'पर्यावरण प्रभाव आकलन' करने वाली कंपनी/संस्था का विवरण और उसके संदर्भ की शर्तें

ii. पर्यावरण प्रभाव आकलन की अनुसूची और जन सुनवाई की तिथि

iii. पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट

iv. पर्यावरण मंजूरी

v. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई मंजूरी और संचालन की सहमति

vi. वन विभाग द्वारा दी गई मंजूरी

vii. विभिन्न क्रम विभागों द्वारा दी गई मंजूरी

viii. भूमि, जल, वायु, वनस्पति और आजीविका पर निष्कर्षण कार्यों के प्रभाव का सारांश

ix. निष्कर्षण के प्रभावों को कम करने के लिए पट्टाधारक द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का सारांश

x. निकासी के अनुसार वायु, ध्वनि और जल प्रदूषण की अनुमेय मात्रा और खनन स्थल पर वायु जल और ध्वनि प्रदूषण की वास्तविक मात्रा

xi. खनन क्षेत्रों में सरकारी अधिकारियों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन

5. उत्पादन:

पट्टाधारकों को सुरक्षा और श्रम कल्याण की न्यूनतम शर्तों का पालन करना और पट्टे में निर्धारित उत्पादन सीमा के तहत काम करना अनिवार्य है। पट्टाधारकों को भी उत्पादन की मात्रा के अनुरूप भुगतान करना होता है। नतीजतन, पट्टा स्तर पर उत्पादन के सभी मानकों में पारदर्शिता आवश्यक है। इस चरण के संदर्भ में, निम्नलिखित जानकारी का सार्वजनिक डोमेन में होना आवश्यक है:

i. खनन योजना और खनन पट्टानामा
ii. खनन स्थल में कार्यरत श्रमिकों की सूची
iii. पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट
iv. आईबीएम और विभाग के पास पट्टाधारक द्वारा दायर मासिक और वार्षिक उत्पादन रिपोर्ट
v. विभाग द्वारा संचालित संबंधित खदान की निरीक्षण रिपोर्ट
vi. विभाग द्वारा पट्टाधारकों को जारी कारण बताओ नोटिस
vii. वसूली की मांग, की गई वसूली
viii. पट्टाधारक द्वारा खदान में किए गए निवेश का विवरण जिसमें मशीनरी पर खर्च की गई राशि, भूमि पर खर्च की गई राशि - खरीद, मुआवजा और पुनर्वास, और प्रबंधन और श्रमिकों को देय वेतन शामिल है।
ix. तृतीय पक्षों से अनुबंधित गतिविधियां, उनके संदर्भ की शर्तें और दरें
x. खनन स्थल में प्रतिदिन दर्ज किए गए पर्यावरण डेटा और निर्धारित मानदंड

6. भुगतान:

पट्टाधारक/ अनुबंध धारक द्वारा निष्कर्षण संबंधी गतिविधियों से सरकार और प्रभावित समुदायों को किए गए भुगतानों को प्रकाशित करके, नागरिक निष्कर्षण उद्योग को वित्तीय रूप से जवाबदेह ठहरा सकते हैं। भुगतान प्रकटीकरण नागरिकों को यह समझने में सक्षम बनाता है कि क्या राजस्व प्राप्त हुआ और किस कीमत पर प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, भुगतान प्रकटीकरण नागरिकों को राज्य द्वारा बुनियादी सेवाओं के प्रावधान के लिए उचित बजटीय आवंटन की अपनी मांग को मजबूत करने में सक्षम बनाता है, जो निकासी से मौद्रिक रूप से प्राप्त हुआ है। इसके लिए यह आवश्यक है कि भुगतानों को संघ/राज्य बजट में रिपोर्ट किए गए कुल आंकड़ों के बजाय परियोजनावार रिपोर्ट किया जाए।

पट्टाधारक द्वारा सरकार को किए गए भुगतानों के प्रकार निम्नलिखित हैं, जिन्हें वैश्विक अनिवार्य प्रकटीकरण मानक के अनुसार प्रकट करना अनिवार्य है (यूरोपीय संघ, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और स्विटजरलैंड में कानून पारित किया गया है) (अनुच्छेद 41.5):

i. उत्पादन अधिकार;
ii. मूल्य वर्धित कर, व्यक्तिगत आय कर या बिक्री कर जैसे उपभोग पर लगाए गए करों को छोड़कर, कंपनियों की आय, उत्पादन या लाभ पर लगाए गए कर
iii. रॉयल्टी
iv. लाभांश
v. हस्ताक्षर, खोज और उत्पादन बोनस
vi. लाइसेंस शुल्क, किराया शुल्क, प्रवेश शुल्क और लाइसेंस और/या रियायतों के लिए अन्य विचार;
vii. बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भुगतान;

उपरोक्त प्रकार के भुगतानों के अलावा, पट्टाधारकों के भुगतान जिन्हें वर्तमान में वैश्विक अनिवार्य प्रकटीकरण मानक के अनुसार प्रकट करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन भारतीय संदर्भ के लिए संदर्भ के साथ वारंट प्रकटीकरण में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. पट्टाधारक द्वारा सरकार को राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट में किया गया योगदान

ii. जिला खनिज फाउंडेशन में किया योगदान
iii. खदान बंद करने की योजना के अनुसार पट्टाधारक द्वारा खदान को बंद करने की लागत
iv. कार्यस्थल पर बुनियादी ढांचे और उपकरणों को तैनात करने में पट्टाधारक द्वारा खर्च की गई लागत
v. मानदंडों के उल्लंघन के लिए पट्टाधारक द्वारा भुगतान किया गया दंड
vi. कर्मचारियों और श्रमिकों को किया गया वेतन भुगतान
vii. भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजे के रूप में किया गया भुगतान और किसको किया गया
viii. पर्यावरण मंजूरी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मंजूरी और वन मंजूरी में निर्धारित शर्तों का पालन करने के लिए पट्टाधारक द्वारा खर्च की गई लागत
ix. पट्टेदार द्वारा श्रमिकों को मुआवजे के लिए किए गए खर्च
x. पट्टाधारक द्वारा खदान में सुरक्षा मानदंडों को बनाए रखने के लिए किए गए खर्च जैसा कि कानून में निर्धारित किया गया है
xi. सुरक्षा/पुलिस सुरक्षा के लिए किया गया खर्च
xii. पट्टाधारक द्वारा राजनीतिक दलों को दिया गया चंदा
xiii. सीएसआर दायित्वों को पूरा करने के लिए पट्टाधारक द्वारा किया गया व्यय
xiv. लेखापरीक्षित खनन प्राप्तियां

7. जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट:

खदान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 प्रत्येक खनन जिले में 2015 के बाद से "खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए काम करने" के उद्देश्य से एक जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की स्थापना को अनिवार्य करता है। डीएमएफ खनन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित उन समुदायों को राहत, पुनर्वास और मुआवजे का विस्तार करने के प्रयास के लिए एक संभावित अवसर के रूप में काम कर सकता है। मॉडल डीएमएफ नियम और एक मॉडल डीएमएफ ट्रस्ट डीड को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है और राज्य सरकारों द्वारा इसे राज्य स्तर पर अधिसूचित किया गया है। हालांकि, डीएमएफ के उपयोग से खनन प्रभावित क्षेत्रों और समुदायों पर कितना सुधार हुआ है,

इस पर फैसला विभाजित है। डीएमएफ के तहत एकत्रित धन के आवंटन, योजना, उपयोग और व्यय में पारदर्शिता की कमी के परिणामस्वरूप डीएमएफ के प्रशासन ढांचे में प्रभावित समुदायों और सीएसओ के खराब प्रतिनिधित्व, निधियों के उपयोग की योजना बनाने में गैर-भागीदारी और गैर-समावेशी प्रक्रियाओं जैसे मुद्दे सामने आए हैं और निर्णय लेने में राजनीतिक हस्तक्षेप, जो आज की स्थिति में डीएमएफ के कार्यान्वयन में बोर्ड सभी जगह में देखी गई प्रणालीगत अपर्याप्तताओं में योगदान दे रहे हैं। परिणामस्वरूप पारदर्शिता उन लोगों के लिए डीएमएफ फंड के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। इस चरण के संदर्भ में, निम्नलिखित जानकारी का सार्वजनिक डोमेन में होना आवश्यक है:

i. पट्टाधारक द्वारा डीएमएफटी में योगदान
ii. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गांवों की सूची
iii. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्तियों/समुदायों की सूची
iv. निम्नलिखित बिंदुओं के आधारभूत मापदंड:

•वायु प्रदुषण

•जल प्रदूषण

• खनन के कारण सिलिकोसिस और अन्य व्यावसायिक रोगों से प्रभावित श्रमिक

• आवश्यक सेवाओं के लिए बजटीय आवंटन - स्वास्थ्य, शिक्षा, जल आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा

v.निधियों के उपयोग के लिए ट्रस्ट की शासकीय परिषद द्वारा प्राप्त प्रस्ताव

vi. मानदंड जिनके आधार पर शासकीय परिषद प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करती है

vii. शासकीय परिषद की संरचना और बैठकों का विवरण

viii. स्वीकृत और अस्वीकृत प्रस्तावों की सूची

viii. तकनीकी और वित्तीय अनुमान; वित्तीय और प्रशासनिक प्रतिबंध; स्वीकृत परियोजनाओं के लिए कार्यादेश

ix. पूर्ण किए गए कार्य के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र

x. व्यक्तिगत और सामूहिक लाभार्थियों की सूची

xi. निम्नलिखित बिन्दुओं के अंतिम मापदंड:

•वायु प्रदुषण

•जल प्रदूषण

• खनन के कारण सिलिकोसिस और अन्य व्यावसायिक रोगों से प्रभावित श्रमिक

• आवश्यक सेवाओं के लिए बजटीय आवंटन - स्वास्थ्य, शिक्षा, जल आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा

8. खदान बंद करना:

पट्टाधारक सतही भूमि को मूल भूमिधारकों को उन्हीं परिस्थितियों में वापस करने के लिए बाध्य हैं जिनके तहत उन्होंने उन्हें प्राप्त किया था। परिणामस्वरूप, इस चरण के संदर्भ में, निम्नलिखित जानकारी को सार्वजनिक डोमेन में होना आवश्यक है:

i. खदान बंद करने की प्रगतिशील योजना

9. v. सुझाए गए अगले चरण

अधिक पारदर्शिता के माध्यम से निष्कर्षण को नागरिकों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए काम कर रहे उन कार्यकर्ताओं और सीएसओ के लिए और सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने पर काम करने वालों के लिए यह आवश्यक है कि वे इस चार्टर की मांग को वास्तविकता बनाने के लिए एक साथ आएं। यह दोनों प्रकार के संगठनों को एक-दूसरे की ताकत को बढ़ाने और उन्नति के लिए सक्षम कर सकता है और इसलिए निष्कर्षण उद्योग के लिए एक प्रभावी, विश्वसनीय और व्यावहारिक पारदर्शिता ढांचा तैयार करता है जो मौजूदा स्थान और तंत्र का उपयोग करता है और उनके बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है।

ऊपर पहचान की गई सूचनाएं केवल सूचना की इच्छा सूची नहीं रहनी चाहिए, जिसकी नागरिक और समूहवाचक प्रकटीकरण की आशा करते हैं। व्यक्त की गई कुछ सूचनाएं पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में साझा करने के लिए अनिवार्य है, जबकि कुछ सूचनाओं के लिए ऐसा कोई

जनादेश मौजूद नहीं है। एक अभियान के रूप में इस सूचना को प्रकट करने के तरीकों को प्रदर्शित करने के लिए कुछ चरणों में सरकार के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। अन्य मामलों में, सूचना को सार्वजनिक करने के लिए सरकार को याचिका दायर करने के लिए वैधानिक प्राधिकरणों और मीडिया के साथ जुड़ने की आवश्यकता होगी।

निम्नलिखित कुछ गतिविधियां हैं जो निष्कर्षण उद्योग में पारदर्शिता की मांग करने वाले अभियान में शामिल होंगी:

i. आरटीआई अधिनियम की धारा 18, के तहत राज्य और केंद्रीय सूचना आयोग को शिकायतें जमा करें ताकि संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण को सार्वजनिक डोमेन में चार्टर में पहचानी गई सूचना को सक्रिय रूप से उपलब्ध कराने का आदेश दिया जा सके क्योंकि यह सार्वजनिक हित में है।
ii. "नीलामी से पहले पूर्व सहमति" के प्रावधान को शामिल करने के लिए खदान खनिज और विकास विनियमन अधिनियम, 1957 में संशोधन करने के लिए सिफारिशों और मांगों के साथ सरकार और संसद सदस्यों को लिखें। 2013 में कानून मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 'पूर्व-विधान नीति' उसी के लिए एक कानूनी आधार है।
iii. निष्कर्षण उद्योग में भ्रष्टाचार को उजागर करने वालों के दृष्टिकोण से विशेष रूप से इसे प्रभावी और लागू करने योग्य बनाने के लिए व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2011 को मजबूत करने के लिए पैरवी करें। नागरिकों को अन्य देशों में प्रावधानों के अनुसार पुरस्कृत किया जाना चाहिए, इस प्रकार उन्हें प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए।
iv. "सरकारों को भुगतान" प्रकटीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक समूह बनाएं, ताकि यह सहमति हो सके कि कौन से भुगतान मांगे जाएं, और अनिवार्य भुगतान प्रकटीकरण को वास्तविकता बनाने के लिए एक पावर मैपिंग हितधारक विश्लेषण करें।
v. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए ऑडिट के दायरे में निष्कर्षण में शामिल कंपनियों की ऑडिट की शुरुआत के लिए पैरवी। आगे कैग द्वारा विकसित सामाजिक ऑडिट के ऑडिट मानकों के अनुसार परियोजनाओं के सामाजिक ऑडिट के संचालन की पैरवी करना और एक उपयुक्त स्तर पर इच्छुक सरकार के साथ एक अगुआई का प्रदर्शन करना।

vi. भारत के लिए निष्कर्षण उद्योग पारदर्शिता पहल (एक्स्ट्रेक्टिव इंडस्ट्री ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव) और ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप का सदस्य बनने और प्रकटीकरण और पारदर्शिता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करने के लिए पैरवी करना

vii. एक मॉडल वेब प्रकटीकरण पोर्टल का विकास करना ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि खनन के सभी चरणों से संबंधित सूचनाओं की मेजबानी के लिए एक एकल पोर्टल को एक मंच के रूप में कैसे विकसित किया जा सकता है। इसके बाद केंद्र और राज्य स्तर पर अनुकरण के लिए इसकी पैरवी की जा सकती है

viii. वर्तमान में प्रकट की जा रही सूचना और खदान डेटा तक पहुँचने के लिए कार्यकर्ताओं, नागरिकों और अभियानों के साथ कार्यशालाओं का संचालन करना और पैरवी के प्रयासों में इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करना

ix. सभी स्तरों पर आवश्यक जानकारी के प्रकटीकरण के लिए खाके (टेम्पलेट) विकसित करना जो सूचना के विवरण को आसन तरीके से संप्रेषित कर सके

x. जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) मॉडल को प्रकटीकरण प्रदर्शित करने के लिए राज्य सरकार/जिला कलेक्टर के साथ काम करना, जिसके अनुकरण के लिए पैरवी की जा सकती है